



GENERAL / FINANCIAL BANKING AWARENESS & STATIC GK

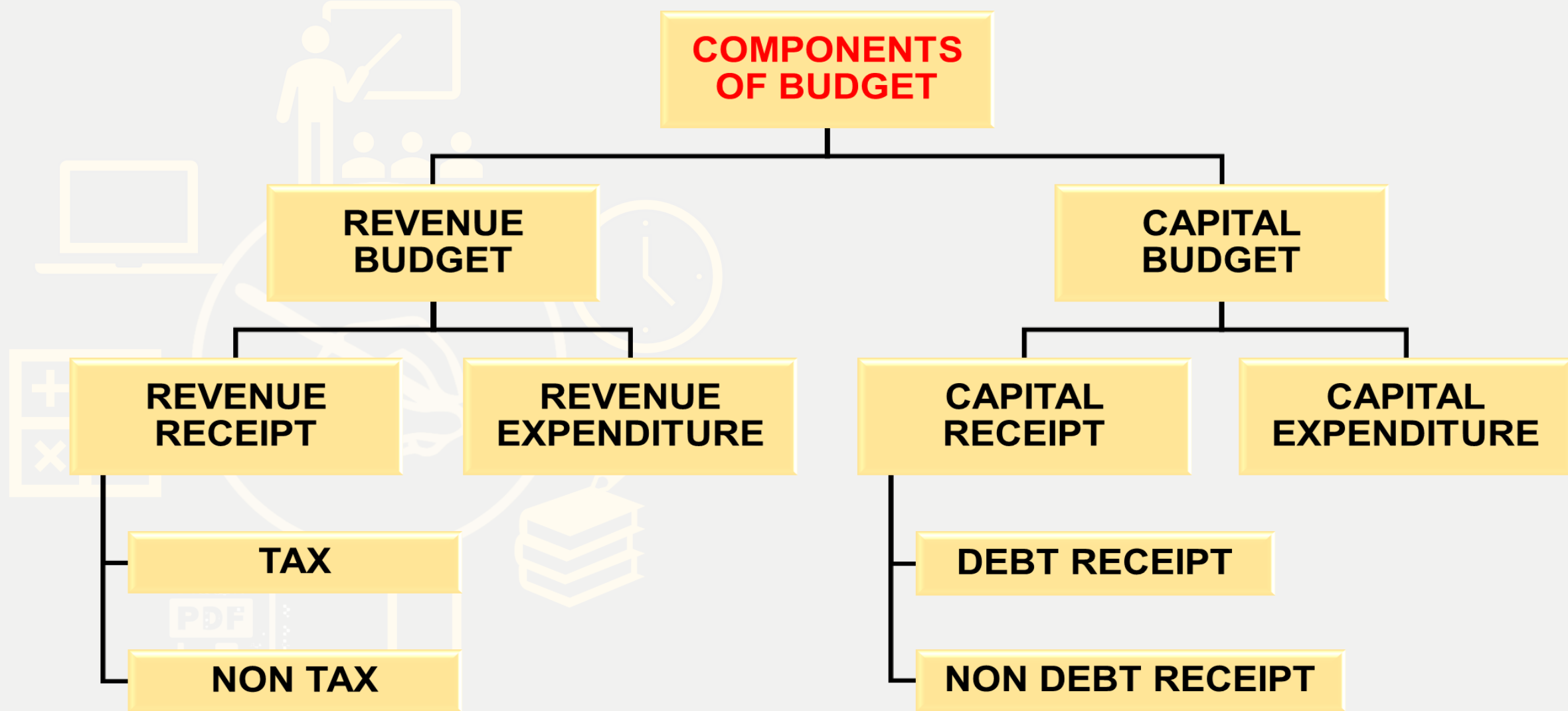
Current Budget

SBI PO 2021 | IBPS PO & CLERK 2021

DAY - 19


1:00 PM





Revenue Expenditure

- **It is regular and recurring in nature.**
- **Expenditure incurred on normal recurring of the government departments and Maintenance of services is treated as revenue expenditure.**
- **Traditionally, all grants given to state governments are treated as revenue expenditure.**

- 
- राजस्व व्यय
 - यह प्रकृति में नियमित और आवर्ती है।
 - सरकारी विभागों की सामान्य आवर्ती और सेवाओं के रखरखाव पर किए गए व्यय को राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है।
 - परंपरागत रूप से, राज्य सरकारों को दिए जाने वाले सभी अनुदानों को राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है।


Capital Expenditure

Capital expenditure refers to the expenditure which either creates an asset or causes a reduction in the liabilities of the Government.

Ex.- Loan to states and Union Territories, Expenditure on Building, Roads, Flyovers, Factories, etc. Purchase of machinery, etc. Repayment of borrowings, etc.

पूंजीगत व्यय से तात्पर्य उस व्यय से है जो या तो संपत्ति बनाता है या सरकार की देनदारियों में कमी का कारण बनता है।

Ex.- राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऋण, भवन, सड़कों, फ्लाईओवर, कारखानों आदि पर व्यय। मशीनरी की खरीद, आदि। उधार की चुकौती,

- 
- **It is non-recurring in nature.**
 - **It is incurred for the acquisition of capital assets.**
 - **It is generally a long period expenditure.**
 - यह प्रकृति में गैर-आवर्ती है।
 - यह पूंजीगत संपत्ति के अधिग्रहण के लिए खर्च किया जाता है।
 - यह आम तौर पर एक लंबी अवधि का खर्च होता है।

Various Indicators of Deficit in the Budget

There can be different types of deficit in a budget depending upon the types of receipts and expenditure.

These are:

Budget Deficit

A budget deficit occurs whenever a government spends more than it makes, which is nearly every year.

* **Budget deficit = Total expenditure – Total receipts**

बजट में घाटे के विभिन्न संकेतक

प्राप्तियों और व्यय के प्रकार के आधार पर बजट में विभिन्न प्रकार के घाटे हो सकते हैं। ये हैं:

बजट घाटा एक बजट घाटा तब होता है जब कोई सरकार जितना खर्च करती है उससे अधिक खर्च करती है।

***बजट घाटा = कुल व्यय - कुल प्राप्तियां**

Revenue Deficit

Revenue is the amount of money that a company actually receives during a specific period, usually from the sale of goods and services to customers. So Revenue deficit is excess of total revenue expenditure of the government over its total revenue receipts.

*** Revenue deficit = Revenue expenditure – Revenue receipts**

Revenue deficit signifies that government's own earning is insufficient to meet normal functioning of government departments and provision of services. So it leads to borrowing and sale of its assets.

राजस्व घाटा

राजस्व वह राशि है जो एक कंपनी वास्तव में एक विशिष्ट अवधि के दौरान प्राप्त करती है, आमतौर पर ग्राहकों को वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री से। इसलिए राजस्व घाटा सरकार के कुल राजस्व व्यय से उसकी कुल राजस्व प्राप्तियों से अधिक है।

- **राजस्व घाटा = राजस्व व्यय - राजस्व प्राप्तियां**

राजस्व घाटा दर्शाता है कि सरकार की अपनी कमाई सरकारी विभागों के सामान्य कामकाज और सेवाओं के प्रावधान को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। तो यह अपनी संपत्ति के उधार और बिक्री की ओर जाता है।

Fiscal Deficit

A fiscal deficit occurs when a government's total expenditures exceed the revenue that it generates, excluding money from borrowings. It is an indication of the total borrowings needed by the government.

*** Fiscal deficit = Total expenditure – Total receipts
(excluding borrowings)**

A deficit is usually financed through borrowing from either the central bank of the country or raising money from capital markets by issuing different instruments like treasury bills and bonds.

राजकोषीय घाटा

राजकोषीय घाटा तब होता है जब सरकार का कुल व्यय उस राजस्व से अधिक हो जाता है जो वह उत्पन्न करता है, उधार से धन को छोड़कर। यह सरकार द्वारा आवश्यक कुल उधारी का एक संकेत है।

राजकोषीय घाटा = कुल व्यय – (उधार को छोड़कर) कुल प्राप्तियां

एक घाटा आमतौर पर देश के केंद्रीय बैंक से उधार लेने या ट्रेजरी बिल और बांड जैसे विभिन्न उपकरणों को जारी करके पूंजी बाजार से धन जुटाने के माध्यम से वित्तपोषित होता है।



Primary Deficit

Primary Deficit that shows the difference between fiscal deficit and interest payments on previous borrowings.

*** Primary Deficit = Fiscal deficit – interest payments**

Primary Deficit shows how much the government has to borrow in the current period to pay interest on borrowings of previous period.

प्राथमिक घाटा

प्राथमिक घाटा जो पिछले उधारों पर राजकोषीय घाटे और ब्याज भुगतान के बीच अंतर को दर्शाता है।

प्राथमिक घाटा = राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान

प्राथमिक घाटा दर्शाता है कि पिछली अवधि के उधार पर ब्याज का भुगतान करने के लिए सरकार को वर्तमान अवधि में कितना उधार लेना है।



Union Budget 2021



Union Minister for Finance & Corporate Affairs, Nirmala Sitharaman presented the Union Budget 2021- 22 in Parliament on 1st February.

Budget proposals for 2021-2022 rest on 6 pillars -

- **Health and Wellbeing.**
- **Physical & Financial Capital, and Infrastructure.**
- **Inclusive Development for Aspirational India.**
- **Reinvigorating Human Capital.**
- **Innovation and R&D.**
- **Minimum Government and Maximum Governance.**

केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री, निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को संसद में केंद्रीय बजट 2021-22 पेश किया।

2021-2022 के बजट प्रस्ताव 6 स्तंभों पर टिके हैं -

- स्वास्थ्य और अच्छाई
- भौतिक और वित्तीय पूंजी, और बुनियादी ढांचा
- आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास
- मानव पूंजी को पुनर्जीवित करना
- नवाचार और अनुसंधान एवं विकास
- न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन

Health and Sanitation / स्वास्थ्य और स्वच्छता

Budget outlay for Health and Wellbeing is **2,23,846 crores** in Budget estimates 2021-22 as against this year's Budget estimates of **Rs 94,452 crores** an increase of **137 percentage**.

बजट अनुमान 2021-22 में स्वास्थ्य और भलाई के लिए बजट परिव्यय 2,23,846 करोड़ है, जबकि इस वर्ष के बजट अनुमान 94,452 करोड़ रुपये 137 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले है।

Health and Sanitation / स्वास्थ्य और स्वच्छता

- A new scheme, titled **PM Atma Nirbhar Swasthya Bharat Yojana**, to be launched with an outlay of **Rs 64,180 crore** over 6 years.
- Under this scheme-
 - Support for **17,788 rural and 11,024 urban Health and Wellness Centers**
 - Setting up integrated public health labs in all districts and **3382 block public health units in 11 states.**
 - Establishing critical care hospital blocks in **602 districts** and **12 central institutions.**
 - Strengthening of the **National Centre for Disease Control (NCDC)**, its regional branches and **20 metropolitan health**

- 6 वर्षों में 64,180 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ पीएम आत्म निर्भर स्वास्थ्य भारत योजना नामक एक नई योजना शुरू की जाएगी।
- इस योजना के तहत-
- 17,788 ग्रामीण और 11,024 शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के लिए सहायता
- 11 राज्यों में सभी जिलों में एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं और 3382 ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों की स्थापना।
- 602 जिलों और 12 केंद्रीय संस्थानों में क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉक की स्थापना।
- राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी), इसकी क्षेत्रीय शाखाओं और 20 महानगरीय स्वास्थ्य निगरानी इकाइयों का सुदृढ़ीकरण।

Health and Sanitation / स्वास्थ्य और स्वच्छता

- Expansion of the Integrated Health Information Portal to all States/UTs to connect all public health labs.
- Operationalization of **17 new Public Health Units** and strengthening of **33 existing Public Health Units** at Points of Entry, that is at **32 Airports, 11 Seaports and 7 land crossings**.
- Setting up of **15 Health Emergency Operation Centers** and **2 mobile hospitals**.

- सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं को जोड़ने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पोर्टल का विस्तार।
- 17 नई सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों का संचालन और प्रवेश के बिंदुओं पर 33 मौजूदा सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों को मजबूत करना, जो कि 32 हवाई अड्डों, 11 बंदरगाहों और 7 लैंड क्रॉसिंग पर है।
- 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर और 2 मोबाइल अस्पताल की स्थापना।

Vaccine / टीका

- Provision of **Rs 35,000 crore** made for Covid-19 vaccine in Budget Estimates 2021-22.
- The Pneumococcal Vaccine, a Made in India product, is presently limited to only **5 states** will be rolled out across the country. This will avert more than **50,000 child** deaths annually.
- बजट अनुमान 2021-22 में कोविड-19 वैक्सीन के लिए **35,000 करोड़ रुपये** का प्रावधान।
- न्यूमोकोकल वैक्सीन, मेड इन इंडिया उत्पाद, वर्तमान में देश भर में केवल 5 राज्यों तक सीमित है। इससे सालाना 50,000 से ज्यादा बच्चों की मौत से बचा जा सकेगा।

Mission Poshan 2.0

To strengthen nutritional content, delivery, outreach, and outcome we will merge the Supplementary **Nutrition Programme and the Poshan Abhiyan** and launch the **Mission Poshan 2.0** , we shall adopt an intensified strategy to improve nutritional outcomes across **112 Aspirational Districts**.

पोषण सामग्री, वितरण, आउटरीच और परिणाम को मजबूत करने के लिए हम पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान का विलय करेंगे और **मिशन पोषण 2.0** लॉन्च करेंगे, हम **112 आकांक्षात्मक जिलों** में पोषण संबंधी परिणामों में सुधार के लिए एक गहन रणनीति अपनाएंगे।

Jal Jeevan Mission (Urban)

- The **Jal Jeevan Mission (Urban)**, will be launched.
- It aims at universal water supply in all **4,378 Urban Local Bodies** with **2.86 crores** household tap connections, as well as liquid waste management in **500 AMRUT cities**.
- It will be implemented over **5 years**, with an outlay of **2,87,000 Crores**.
- जल जीवन मिशन (शहरी) शुरू किया जाएगा।
- इसका उद्देश्य सभी 4,378 शहरी स्थानीय निकायों में 2.86 करोड़ घरेलू नल कनेक्शन के साथ-साथ 500 अमृत शहरों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन के साथ सार्वभौमिक जल आपूर्ति करना है।
- इसे 2,87,000 करोड़ के परिव्यय के साथ 5 वर्षों में लागू किया जाएगा।

Education / शिक्षा

- **100 new Sainik Schools** to be set up.
- **750 Eklavya schools** to be set up in tribal areas.
- **A Central University** to come up in **Ladakh**.

- 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे
- 750 एकलव्य स्कूल आदिवासी क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे
- लद्दाख में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।

Infrastructure / आधारभूत संरचना

Vehicle scrapping policy to phase out old and unfit vehicles – All vehicles to undergo a fitness test in automated fitness centers every **20 years (personal vehicles), every 15 years (commercial vehicles).**

पुराने और अनुपयुक्त वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर व्हीकल स्कैपिंग पॉलिसी - सभी वाहनों को हर 20 साल (निजी वाहन), हर 15 साल (वाणिज्यिक वाहन) में स्वचालित फिटनेस सेंटर में फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा।

- Highway and road works announced in **Kerala, Tamil Nadu, West Bengal, and Assam.**
- **National Asset Monetising Pipeline** launched to monitor Asset Monetization Process.
- National Rail Plan created to bring a future-ready Railway system by **2030, 100% electrification** of Railways to be completed by **2023.**
- केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और असम में राजमार्ग और सड़क कार्यों की घोषणा की गई।
- संपत्ति मुद्रिकरण प्रक्रिया की निगरानी के लिए राष्ट्रीय संपत्ति मुद्रिकरण पाइपलाइन शुरू की गई।
- 2030 तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे प्रणाली लाने के लिए बनाई गई राष्ट्रीय रेल योजना 2023 तक रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा किया जाएगा।

- Metro services announced in **27 cities**, plus additional allocations for **Kochi Metro, Chennai Metro Phase 2, Bengaluru Metro Phase 2A and B, Nashik and Nagpur Metros.**
- **National Hydrogen Mission** to be launched to generate hydrogen from Green Power Sources.
- Recycling capacity of ports to be doubled by **2024.**
- 27 शहरों में मेट्रो सेवाओं की घोषणा, साथ ही कोच्चि मेट्रो, चेन्नई मेट्रो फेज 2, बेंगलुरु मेट्रो फेज 2ए और बी, नासिक और नागपुर मेट्रो के लिए अतिरिक्त आवंटन।
- हरित ऊर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन शुरू किया जाएगा।
- बंदरगाहों की पर्यवेक्षण क्षमता 2024 तक दोगुनी की जाएगी।

- **Gas pipeline project to be set up in Jammu and Kashmir.**
- **Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (LPG scheme) to be extended to cover 1 crore more beneficiaries.**
- जम्मू-कश्मीर में गैस पाइपलाइन परियोजना स्थापित की जाएगी।
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (एलपीजी योजना) का विस्तार 1 करोड़ और लाभार्थियों को कवर करने के लिए किया जाएगा।

Tax / कर

- **No IT filing** for people **Above 75 years** who get pension and earn interest from deposits.
- The reopening window for IT assessment cases reduced from **6 to 3 years**.
- However, in case of **Serious Tax Evasion Cases (Rs. 50 lakh or more)**, it can go up to **10 years**.

- 75 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए कोई आईटी फाइलिंग नहीं जो पेंशन प्राप्त करते हैं और जमा से ब्याज कमाते हैं।
- आईटी मूल्यांकन मामलों के लिए फिर से खोलने की खिड़की 6 साल से घटाकर 3 साल कर दी गई है।
- हालांकि, गंभीर कर चोरी के मामलों (50 लाख रुपये या अधिक) के मामले में, यह 10 साल तक जा सकता है।

- Affordable, **Housing Projects** to get a **tax holiday** for one year.
 - Compliance Burden of Small Trusts whose Annual Receipts do not exceed **Rs. 5 crores** to be eased.
 - Duty of Copper Scrap reduced to **2.5%**.
 - Custom duty on **gold and silver** to be rationalized.
-
- अफोर्डेबल, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर एक साल के लिए टैक्स हॉलिडे।
 - छोटे ट्रस्टों का अनुपालन बोझ जिनकी वार्षिक प्राप्तियां रुपये से अधिक नहीं हैं ,5 करोड़ की छूट दी जाएगी।
 - कॉपर स्क्रेप का शुल्क घटाकर 2.5% किया गया।
 - सोने और चांदी पर सीमा शुल्क को युक्तिसंगत बनाया जाए।

- Duty on **Naphtha** reduced to **2.5%**.
- Duty on **solar inverters** raised from **5% to 20%**, and on **solar lanterns** from **5% to 15%**.
- All **Nylon products** charged with **5%** customs duty.
- **Tunnel Boring Machines** to attract Customs duty of **7%**.
- Customs duty on **Cotton** raised from **0 to 10%**.
- Agriculture infrastructure and Development Cess Proposed on certain items including **urea, apples, crude soya bean and sunflower oil, crude palm oil, Kabuli chana, and peas**.

- नेफ्था पर शुल्क घटाकर 2.5% किया गया।
- सोलर इनवर्टर पर ड्यूटी 5% से बढ़ाकर 20% और सोलर लालटेन पर 5% से बढ़ाकर 15% कर दी गई है।
- सभी नायलॉन उत्पादों पर 5% सीमा शुल्क लगाया गया।
- टनल बोरिंग मशीन पर 7% सीमा शुल्क लगेगा।
- कपास पर सीमा शुल्क 0 से बढ़ाकर 10% किया गया।
- यूरिया, सेब, कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल, कच्चे पाम तेल, काबुली चना और मटर सहित कुछ वस्तुओं पर कृषि अवसंरचना और विकास उपकर प्रस्तावित है।

Economy and Finance / अर्थव्यवस्था और वित्त

- The Fiscal Deficit stands at **9.5%** of the **GDP**; estimated to be **6.8%** in **2021-22**.
- Proposal to allow States to raise borrowings up to **4% of GSDP** this year.
- A Unified Securities Market Code to be created, consolidating provisions of the SEBI Act, Depositories Act, and two other laws.

- राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 9.5% है; 2021-22 में 6.8% होने का अनुमान है।
- राज्यों को इस साल जीएसडीपी के 4% तक उधार लेने की अनुमति देने का प्रस्ताव।
- सेबी अधिनियम, डिपॉजिटरी अधिनियम और दो अन्य कानूनों के प्रावधानों को समेकित करते हुए एक एकीकृत प्रतिभूति बाजार कोड बनाया जाना है।

- Proposal to Increase **FDI limit** from **49% to 74%**.
- An **Asset Reconstruction Company** will be set up to take over stressed loans.
- Deposit insurance increased from **Rs 1 lakh to Rs 5 lakh** for bank depositors.
- Proposal to decriminalize Limited Liability Partnership Act of 2008.
- **Two PSU bank** and **One general insurance firm** to be Disinvested this year.
- An **IPO of LIC** to debut this fiscal Strategic sale of **BPCL, IDBI Bank, Air India** to be completed.

- एफडीआई की सीमा 49 फीसदी से बढ़ाकर 74 फीसदी करने का प्रस्ताव।
- स्ट्रेस्ड लोन लेने के लिए एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की स्थापना की जाएगी।
- बैंक जमाकर्ताओं के लिए जमा बीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया गया।
- 2008 के सीमित देयता भागीदारी अधिनियम को अपराध से मुक्त करने का प्रस्ताव।
- इस वर्ष दो पीएसयू बैंक और एक सामान्य बीमा फर्म का विनिवेश किया जाएगा। एलआईसी का आईपीओ इस वित्तीय वर्ष में बीपीसीएल, आईडीबीआई बैंक, एयर इंडिया की रणनीतिक बिक्री को पूरा करने के लिए पूरा किया जाएगा।


Agriculture / कृषि

- Agriculture infrastructure fund to be made available for **APMCs (Agricultural Produce Market Committee)** for augmenting their infrastructure **1,000** more Mandis to be integrated into the **E-NAM** market place.
- **Five** major fishing hubs, including **Chennai, Kochi, and Paradip**, to be developed a multipurpose **Seaweed Park** to be established in **Tamil Nadu**.

- एपीएमसी (कृषि उपज बाजार समिति) को उनके बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए 1,000 और मंडियों को ई-एनएएम बाजार में एकीकृत करने के लिए कृषि अवसंरचना कोष उपलब्ध कराया जाएगा।
- चेन्नई, कोच्चि और पारादीप सहित पांच प्रमुख मछली पकड़ने के केंद्रों को तमिलनाडु में स्थापित करने के लिए एक बहुउद्देश्यीय समुद्री शैवाल पार्क विकसित किया जाना है।

Employment / रोज़गार

- A portal to be launched to maintain information on **Gig workers** and **Construction workers**.
- Social security to be extended to **Gig and Platform workers**.
- Margin capital required for loans via Stand-up India scheme reduced from **25% to 15% for SCs, STs, and women**.

- 
- गिग वर्कर्स और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की जानकारी बनाए रखने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा।
 - गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी।
 - स्टैंड-अप इंडिया योजना के माध्यम से ऋण के लिए आवश्यक मार्जिन पूंजी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए 25% से घटाकर 15% कर दी गई है।


BUDGET HIGHLIGHTS

- **First digital Budget** in the history of India.
- **Vehicle Scrapping Policy.** Vehicle Fitness Test after 20 years in case of Personal vehicle and 15 years in case of commercial vehicles.
- **64,180 crores** allocated for New Health Schemes.
- **35,000 crores** allocated for Covid Vaccine.
- **7 Mega Textile** Investment parks will be launched in 3 years.

- **5.54 lakh crore** provided for Capital Expenditure.
- **1.18 lakh crore** for Ministry of Roads.
- **1.10 lakh crore** allocated to Railways.
- **Proposal to amend Insurance Act. Proposal to increase FDI from 49% to 74 %.**
- **Deposit Insurance cover (DICGC Act 1961 to be amended). Easy and time bound access of deposits to help depositors of stress banks.**
- **Proposal to revive definition of 'Small Companies' under Companies Act 2013. Capital less than 2 Cr. and Turnover Less than 20 Cr.**
- **Disinvestment: IPO of LIC, Announced Disinvestment of**

- **Direct and Indirect tax**
- **Senior Citizens: Reduced Compliance burden. 75 years and above. Proposal not to file ITR if only pension income and interest income.**
- **Reduction in time for IT Proceedings: Reopening of Assessments period reduced from 6 years to 3 years except in cases of serious tax evasion cases**
- **Proposal to constitute 'Dispute Resolution Committee'. (Taxable income 50 lakhs and disputed income 10 lakh).**
- **National Faceless Income Tax Appellate Tribunal Centre**
- **Relaxations to NRI: Propose to notify rules for removing hardship for double taxation.**

- **Tax Audit Limit:** Proposal of tax audit increased from 5 Cr. to 10 cr. (Only for 95% digitized payments business)
- Propose to provide relief on advance tax liability on dividend income.
- Propose to include tax holidays for Aircraft leasing companies
- Prefiling of returns (**Salary, Tax payments, TDS etc.**) Details of Capital gains from listed Securities, dividend income, etc. will be prefilled.
- Small Charitable Trusts. Increased from **1 crore to 5 crores** (Compliance limit)
- Late deposit of employee's contribution by employer will not be allowed as deduction

- 
- **Incentive to startup:** Tax holiday exemption for one more year Duties reduced on various textile, chemicals and other products .
 - **Gold and Silver (BCD reduced)**
 - **Agriculture Products:** Custom duty increased on cottons, silks, alcohol etc.

Q 1- Who presents Budget in Parliament?

Q1- संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है ?



- 1. Prime Minister**
- 2. Finance Minister**
- 3. Home Minister**
- 4. President of
India**

Q 2 - India's first-ever budget was presented by _____?

Q 2 - भारत का पहला बजट _____ द्वारा प्रस्तुत किया गया था?

- 1. James Wilson**
- 2. Jawaharlal Nehru**
- 3. Lord Mountbatten**
- 4. C Rajagopalachari**

Q 3- Budget 2021-22 proposals to rest on six pillars. Which of the following is not among them?

Q 3- बजट 2021-22 में छह स्तंभों पर आराम करने का प्रस्ताव है। निम्नलिखित में से कौन उनमें से नहीं है?

- 1. Health & well being**
- 2. Minimum Government, Maximum Governance**
- 3. Innovation and R&D**
- 4. Agricultural Development**

Q 4- What is the total budget outlay for health & well being?

Q 4- स्वास्थ्य और कल्याण के लिए कुल बजट परिव्यय क्या है?

**1. 2.23 lakh
crore**

**2. 5.06 lakh
crore**

**3. 1.89 lakh
crore**

4. 4.35 lakh

Q 5- According to the budget, how much amount is allocated for Covid Vaccine?

Q 5- बजट के अनुसार कोविड वैक्सीन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है?

- 1. 20,000 crore**
- 2. 15,000 crore**
- 3. 35,000 crore**
- 4. 30,000 crore**

Q 6- How much amount is allocated for PM Atmanirbhar Swasth Bharat Yojana?

Q 6- पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है?

1. 64,180 crore
2. 89,634 crore
3. 70,000 crore
4. 65,000 crore

Q 7- In Union Budget 2021, how much amount is allocated for Railways?

Q 7- केंद्रीय बजट 2021 में रेलवे के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है?

1. 1,00,000 crore
2. 3,25,000 crore
3. 1,10,055 crore
4. 2,30,345 crore

Q 8- Ujjawala Scheme has been extended to how many more districts?

Q 8- उज्जवला योजना का विस्तार कितने और जिलों में किया गया है?

1.110

2.120

3.160

4.100

Q 9 - How much custom duty on cotton and auto parts increased respectively?

Q 9 - कपास और ऑटो के पुर्जों पर क्रमशः कितनी सीमा शुल्क में वृद्धि हुई?

1. 20% & 10%
2. 10% & 25%
3. 10% & 15%
4. 25% & 30%

Q 10- Which company's IPO will be launched in 2021-22 as a part of the Government's disinvestment strategy?

Q 10- सरकार की विनिवेश रणनीति के तहत किस कंपनी का IPO 2021-22 में लॉन्च किया जाएगा?

1. **IDBI**
2. **LIC**
3. **Air India**
4. **SBI**

Q 11- Union Budget for 2020-21 announced an increase in Foreign Direct Investment (FDI) limit in insurance from 49% to _____?

Q 11- 2020-21 के केंद्रीय बजट ने बीमा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा को 49% से बढ़ाकर _____ करने की घोषणा की?

1. 71%
2. 72%
3. 73%
4. 74%

Q 12- Budget for 2021-22 announced voluntary vehicle scrapping policy to phase out old and polluting vehicles. After how many years fitness of commercial vehicles will be checked for the same?

Q 12- 2021-22 के बजट में पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाने के लिए स्वैच्छिक वाहन स्क्रेपिंग नीति की घोषणा की गई। इसके लिए कितने वर्षों के बाद वाणिज्यिक वाहनों की फिटनेस की जांच की जाएगी?

1. 20
2. 10
3. 15
4. 12

Q 13- In Budget 2021, National Infrastructure Pipeline was expanded to cover 7400 projects. What is the capital expenditure announced to fund the same?

Q 13- बजट 2021 में, 7400 परियोजनाओं को कवर करने के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन का विस्तार किया गया था। उसी को निधि देने के लिए घोषित पूंजीगत व्यय क्या है?

1. **Rs 2.54 lakh crore**
2. **Rs 3.54 lakh crore**
3. **Rs 4.54 lakh crore**
4. **Rs 5.54 lakh crore**

Q 14- How many mega-investment textile parks will be established over 3 years?

Q 14- 3 वर्षों में कितने मेगा-इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे?

1. 10
2. 5
3. 7
4. 9

Q 15- FM Nirmala Sitharaman proposes to setup an ARC for NPA Management.

What does 'R' refers to in ARC?

**Q 15- FM निर्मला सीतारमण ने NPA प्रबंधन के लिए ARC स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है।
ARC में 'R' का क्या अर्थ है?**

- 1. Recapitalization**
- 2. Retail**
- 3. Reconstruction**
- 4. Reforms**

Q 16- What is the disinvestment target for FY22?

Q 16- FY22 के लिए विनिवेश लक्ष्य क्या है?

- 1. 1.75 lakh crore**
- 2. 1.60 lakh crore**
- 3. 2 lakh crore**
- 4. 1.90 lakh crore**

Q 17- FM Nirmala Sitharaman announced to protect whom from double taxation in Union Budget 2021?

Q 17- FM निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021 में किसे दोहरे कराधान से बचाने की घोषणा की?

- 1. Indian Citizens**
- 2. Foreigners**
- 3. NRIs**
- 4. All of the above**

Q 18- How many Sainik schools will be setup in partnership with private schools, NGOs and states?

Q18- निजी स्कूलों, गैर सरकारी संगठनों और राज्यों के साथ साझेदारी में कितने सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे?

1. 75
2. 100
3. 50
4. 125

Q 19- As per the budget, central university to be set up in which of the following state/UT?

Q 19- बजट के अनुसार, निम्नलिखित में से किस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी?

- 1. Kerala**
- 2. J&K**
- 3. Tamil Nadu**
- 4. Ladakh**

Q 20- How much amount is allocated for Jal Jeevan Mission over 5 years?

Q 20- 5 वर्षों में जल जीवन मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है?

1. 3.45 lakh crore
2. 1.98 lakh crore
3. 2.87 lakh crore
4. 3.79 lakh crore

